

(ग) इस समय आकर अधिनियम के अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूरे किये गये वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन तक ग्रेजुटी में कर छूट रखी गई है परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। यह सीमाये सरकारी कर्मचारियों और सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित दूसरे कर्मचारियों के बीच समानता रखने के लिए निर्धारित की गई है। ग्रेजुटी पुनर्गठन पर पूर्ण छूट देने की स्थिति में दुरुपयोग की संभावनाएं हैं।

एम० एस० शूज इंस्ट लिमिटेड का सार्वजनिक निर्गम

5311. श्री जी० वाई० कुण्डान: क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश मर्चेंट बैंकर्स ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) पर हाल के एम० एस० शूज लिमिटेड के सार्वजनिक निर्गम, जो कि न्यायगत हो गया है, के मामले में पूरी मनमानी करने का आरोप लगाया है जैसाकि हाल ही में कुछ अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विगत में सेबी को विभिन्न अन्य कंपनियों के हेराफेरी वाले निर्गमों के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

लेकिन उन पर कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई; ऐसा क्यों किया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान, जब सभी प्रकार के संदिग्ध सार्वजनिक निर्गम बाजार में आए हैं तब सेबी ऐसी सुस्पष्ट धोखाधड़ी वाले एक भी मामले को न पकड़वाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सेबी ने अंतर्गो लेन-देन जोकि आर्थिक सुधारों संबंधी उद्यमीकरण के त्वगू होने के बाद बाजार में आने वाले प्रीमियम वाले लगभग प्रत्येक निर्गम के संबंध में अत्यधिक प्रचलित है, के लिए गत चार वर्षों से आज तक एक भी मर्चेंट बैंकर को काली सूची में न डालने अथवा किसी प्रवर्तक के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मुर्ती): (क) से (घ) सूचना एक्टर की जा रही है और सप्ताह-पटल पर रख दी जाएगी।

Shapes and sizes of various coins

5312. SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government contemplate

any steps to rationalise the shapes and sizes of various coins and currency to remove confusion;

(b) if so, whether a large number of complaints/representations also received in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) by when the new coins would be brought out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (d) The Government is considering a proposal for replacement of existing currency/bank notes by an altogether new design of notes. Based on some complaints received from public as well as suggestion made by RBI, proposal for changing shape and size of some coins is also under examination.

Shortage of Non-Judicial Stamp Papers

5313. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Govt.'s attention has been drawn to large scale complaints of shortage and black-marketing of small denomination non-judicial stamp papers;

(b) if so, what action has been taken to ensure adequate supply of these stamp papers as the same are required by public for various purposes on a day to day basis;

(c) whether Government would consider vending these stamp papers through Post Offices just like share transfer stamps; and

(d) if so, by when; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) The shortage of Non-judicial stamp papers is due to production capacity constraints of the security Printing Presses and also abnormal increase in the demand during the recent years.